अपराध के खिलाफ लड़ाई में मदद

मौजूदा विधेयक का स्वरूप कुछ ऐसा रखा गया है कि इसे इस स्पष्ट मकसद तक सीमित रखना मुश्किल लगता है। उदाहरण के लिए यही देखें कि सैंपल इकट्ठा करने का पुलिस का दायरा कितना बढ़ा दिया गया है।

अमन सिंह।।

विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद अपराधियों की पहचान से जुड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर (आइडेंटिफिकेशन) बिल 2022 लोकसभा में पारित कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की शंकाओं को खारिज करते हुए आश्वस्त किया कि सरकार इस बिल का संभावित दुरुपयोग रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी, लेकिन बिल को जिस तरह से ड्राफ्ट किया गया है और जिस तरह के प्रावधान इसमें डाले गए हैं, उन्हें देखते हुए इस पर सवाल उठने लाजिमी हैं। हालांकि यह बिल 1920 में बनाए गए जिस प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट की जगह लागू किया जाना है, वह सचमुच पुराना पड़ चुका है। उसके तहत गिरफ्तार व्यक्तियों के सिर्फ फिंगर फुट प्रिंट्स ही लिए जा सकते हैं। इस बीच हुए तकनीकी विकास के अनुरूप पुलिस के तौर–तरीकों में भी बदलाव आवश्यक हो गए हैं। दुनिया के अन्य देशों में भी जांच एजेंसियां बायोमीट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं। इनसे अपराध के खिलाफ लड़ाई में मदद भी मिलती है। लेकिन मौजूदा विधेयक का स्वरूप कुछ ऐसा रखा गया है कि इसे इस स्पष्ट मकसद तक सीमित रखना मुश्किल लगता है।

उदाहरण के लिए यही देखें कि सैंपल इकट्ठा करने का पुलिस का दायरा कितना बढ़ा दिया गया है। सात साल से ज्यादा सजा वाले आरोपों में गिरफ्तार सभी लोग इसकी जद में आ जाते हैं, चाहे उनके खिलाफ आरोप साबित हो या न हो, चाहे वे संदेह के आधार पर या एहतियातन ही क्यों न गिरफ्तार किए गए हों।

कायदे से, जो लोग सात साल से कम सजा वाले मामलों में पकड़े गए हों, वे सैंपल देने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन अपने देश में पुलिस की जो छवि है, उसमें थाने में लाया गया कोई सामान्य व्यक्ति पुलिस के आदेश मानने से इनकार कर पाएगा, यह सोचना भी कठिन है। बिल में इस मुश्किल का आसान हल यह हो सकता था कि मजिस्ट्रेट की इजाजत से बायोमीट्रिक सैंपल लेने की व्यवस्था कर दी जाती। मगर ऐसी सावधानी की जरूरत बिल ड्राफ्ट करते हुए महसूस नहीं की गई। यही नहीं, इकट्ठा किए गए डेटा के दुरुपयोग या उन्हें अनधिकृत तौर पर लीक किए जाने की आशंका को दूर करने की भी कोई व्यवस्था बिल में नहीं है। इसके अलावा श्मेजरमेंटश की सटीक परिभाषा के अभाव में यह डर भी बना हुआ है कि सीआरपीसी की धारा 53 और 53–ए के सहारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की सलाह पर, नारको एनालिसिस और फेशियल रेकग्निशन जैसी उन प्रक्रियाओं के लिए भी गुंजाइश बना ली जाएगी, जो बेहतर कानूनी तौर–तरीकों की श्रेणी में नहीं आतीं। इस बिल के साथ बहुत सारे किंतु–परंतु जुड़े हुए हैं। विपक्ष की ओर से उठाई जा रही आपत्तियों को विरोध की उसकी आदत मानकर खारिज करना उचित नहीं होगा। उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बिल से जुड़े हर पहलू पर ज्यादा बारीकी से विचार–विमर्श होगा और इसकी त्रुटियों को दूर कर लिया जाएगा।

सृष्टि की रक्षा

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाकर हिंदू बनाना शास्त्रों के अनुसार किस तरह उचित है? गैर हिंदू व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाकर हिंदू बनाए जाने को लेकर दिल्ली स्थित ध्यान आश्रम के धर्म गुरु योगी अश्विनी का कहना है कि शास्त्रों में धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उनका कहना है, शास्त्र करीब साढ़े चार हजार साल पहले लिखे गए थे। उन दिनों सिर्फ सनातन धर्म था जिसका उद्देश्य वेदों और सृष्टि की रक्षा करना था। उन दिनों कोई अन्य धर्म नहीं था इसलिए शास्त्रों में धर्म परिवर्तन को लेकर कोई बात नहीं कही गई। यह तथ्य है कि आज जो इतने सारे धर्म और जातियां दिखती हैं वह शास्त्रों के लिखे जाने के बाद बनी हैं। खासकर ईसाई और इस्लाम।

संपादकीय

आम लोगों पर मार

भारत भी इससे अछूता नहीं है, जहां महंगाई रिजर्व बैंक के ऊपरी दायरे से भी आगे निकल चुकी है। इस बीच, भारत में औद्योगिक उत्पादों की मांग, उत्पादन और निवेश में सुस्ती बनी हुई है। कई वैश्विक और घरेलू संस्थाएं चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी दर के अनुमानों में डेढ़ से दो फीसदी की कटौती कर चुकी हैं। लेकिन इकॉनमी के मैनेजर ऊंट की तरह रेत में सिर छुपाए तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में, महंगाई को काबू में करने का दुनिया के अधिकांश देशों पर दबाव है। महामारी के दौरान डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा और मांग–निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन देशों ने राजकोषीय सहायता में वृद्धि की थी। इसके साथ उदार मौद्रिक नीति अपनाई थी। अब उन्हें यह नीति वापस लेनी होगी। कर्ज की दरें भी बढ़ानी होंगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में ऐसा करने से अर्थव्यवस्थाएं बेपटरी हो सकती हैं और यहां तक कि मंदी में भी फंस सकती हैं। दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील देशों या उभरती हुई अर्थव्यवस्था के मैनेजरों के लिए यह गंभीर दुविधा की स्थिति है। वे तय नहीं कर पा रहे कि महंगाई से निपटें या अर्थव्यवस्था को संभालें? यह भी सच है कि यूक्रेन युद्ध रुके बिना उनका कोई भी फैसला बहुत प्रभावी नहीं होगा। दरअसल, युद्ध रोकने के लिए राजनय और कूटनीति को आगे करना होगा, जिसकी गंभीर पहल कहीं नहीं दिख रही। यह वैश्विक नेतृत्व खासकर बड़े और ताकतवर पश्चिमी देशों के नेतृत्व की नाकामी है। सवाल यह है कि क्या इससे तूफान शांति से गुजर जाएगा?

दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर सिर्फ 2.6 फीसदी रहने का अनुमान है, जो उसके पिछले पूर्वानुमान 3.6 फीसदी से एक फीसदी कम है।

कई देश संकट में

आनंद प्रधान।।

रूस–यूक्रेन युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। पिछले दो सालों से कोरोना महामारी से पस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाल के महीनों में सुधार के संकेत दिख रहे थे, लेकिन रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण उसके पटरी से उतरने का खतरा बढ़ गया है। यही नहीं, चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों और उससे निपटने के लिए लगाए गए सख्त लॉकडाउन से वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा, गैस–पेट्रोल की ऊंची कीमतों और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बेकाबू महंगाई दर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस साल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 4.7 फीसदी की वृद्धि के अपने पिछले पूर्वानुमान को डेढ़ फीसदी से ज्यादा घटाकर सिर्फ तीन फीसदी कर दिया है। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन (अंकटाड) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर सिर्फ 2.6 फीसदी रहने का अनुमान है, जो उसके पिछले पूर्वानुमान 3.6 फीसदी से एक फीसदी कम है।

उधर, विश्व बैंक और आईएमएफ ने भी रूस–यूक्रेन युद्ध को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महामारी के बाद दूसरा बड़ा झटका बताते

हुए उसकी रफ्तार धीमी पड़ने और रूस और यूक्रेन सहित मध्य यूरोप और मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के मंदी की चपेट में आने की चेतावनी दी है। यही नहीं, युद्ध के कारण खाद्यान्नों खासकर गेहूं और वनस्पति तेलों की कीमतों में तेज उछाल से कई विकासशील और गरीब देशों में श्रीलंका की तरह के हालात पैदा होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है।

रूस और यूक्रेन गेहूं, मक्के और खाद्य तेलों के दुनिया के तीन बड़े निर्यातकों में से हैं। रूस और यूक्रेन अकेले दुनिया का लगभग तीस फीसदी गेहूं निर्यात करते हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका के कई देश रूस और यूक्रेन के गेहूं पर निर्भर हैं। इसी तरह रूस उर्वरकों में नाइट्रोजन का दुनिया का सबसे बड़ा, पोटैशियम का दूसरा सबसे बड़ा और फॉस्फोरस का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। लेकिन युद्ध के कारण एक तो काला सागर से व्यापार ठप है। दूसरे, पश्चिमी देशों ने रूस पर वित्तीय और व्यापार संबंधी पाबंदियां लगा रखी हैं। इससे गेहूं, खाद्य तेलों और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। नतीजा यह कि युद्ध शुरू होने के बाद सिर्फ एक महीने में वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों में लगभग 20 फीसदी और मक्के की कीमतों में 19 फीसदी की रेकॉर्डतोड़ उछाल दर्ज की गई है। विश्व खाद्य संगठन (एफएओ) के मुताबिक, मार्च में अनाजों की कीमतों में लगभग 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह फरवरी के बाद से खाद्य तेलों में भी 25 फीसदी तक की उछाल आई है।

जैसे इतना ही काफी न हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के बीच बढ़ती मांग की वजह से पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में पहले से ही तेजी आनी शुरू हो गई थी। लेकिन युद्ध ने उसमें आग लगा दी। यूं तो कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिर दिख रही हैं, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा है। कच्चे तेल और साथ में, अनाजों, खाद्य तेलों की कीमतों में इस तेजी का सीधा असर दुनिया के अधिकांश देशों में बेकाबू हो रही महंगाई दर के रूप में दिख रहा है, जिससे अब लगभग सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतें प्रभावित हो रही हैं।

सूडोकु नवताल-5396

सरल

		2				1		
				2	5	7	3	
	9	4		6	7			2
	5		4		3			9
	8			9			7	
1			6		8		2	
6			7	4		9	5	
	4	5	8	3				
		8				6		

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5395 का हल

9	1	6	2	3	7	4	5	8
8	2	3	4	5	9	1	7	6
4	5	7	1	6	8	3	9	2
5	6	8	7	1	2	9	3	4
1	7	4	9	8	3	2	6	5
2	3	9	5	4	6	8	1	7
7	4	1	8	9	5	6	2	3
3	8	5	6	2	1	7	4	9
6	9	2	3	7	4	5	8	1

अपना ब्लॉग

ऊंची मुद्रास्फीति दर कतई अच्छी खबर नहीं

मोहन। महंगाई के कारण लोग उपभोग में कटौती करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसका असर निवेश पर पड़ता है। इस तरह उपभोग–मांग–निवेश पर निर्भर आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। जाहिर है कि महामारी की मार से मंदी की चपेट में आई उस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ऊंची मुद्रास्फीति दर कतई अच्छी खबर नहीं है, जो कुछ महीनों से पटरी पर लौटती हुई दिख रही थी। यही नहीं, आसमान छूती महंगाई खासकर अनाजों, खाद्य तेलों और पेट्रोल–गैस की कीमतें राजनीतिक रूप से भी अत्यधिक ज्वलनशील मुद्दा हैं। अगर रूस–यूक्रेन युद्ध जल्दी नहीं रुका और महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो श्रीलंका और कजाखिस्तान जैसे हालात मध्य–पूर्व, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका के कई देशों में दिख सकते हैं। याद रहे कि 2011 की 'अरब क्रांति' के पीछे एक बड़ा कारण महंगाई खासकर अनाजों की कीमतों में वृद्धि भी थी।